SKU शोध संचार

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

अंक-3, खण्ड-2, अप्रैल - जून 2025 E-ISSN : 2584-2900

उद्यमिता विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका

आशीष कुमार पचौरी
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

यह शोध पत्र भारत में उद्यमिता विकास के संदर्भ में सरकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करता है। उद्यमिता किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ इस क्षेत्र को सशक्त बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आर्थिक उदारीकरण (1991) से लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान (2020-24) तक, केंद्र और राज्य सरकारों ने वित्तीय पहुँच, तकनीकी नवाचार, बाज़ार सहयोग, और नियामकीय सुधार को लक्षित करते हुए अनेक नीतियाँ संचालित की हैं। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 2023-24 तक 22 करोड़ ऋण खातों के माध्यम से सूक्ष्म-स्तर पर स्वरोज़गार को बल दिया, जबकि स्टार्ट-अप इंडिया ने 1.4 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को टैक्स-छूट, फ़ंड-ऑफ़-फ़ंड और श्रेणी-I AIF निवेश से जोड़ा। स्टैंड-अप इंडिया एवं विभिन्न महिला-केंद्रित योजनाएँ सामाजिक-आर्थिक समावेशन में सहायक रहीं। तथापि, योजना-जानकारी का असमान प्रसार, ऋण स्वीकृतियों में भौगोलिक विषमता, और उभरते उद्यमियों में कौशल-अंतर जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

शोध निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यदि सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित एकल-खिड़की पोर्टल, स्थानीय-स्तरीय मेंटरशिप नेटवर्क, और प्रभावी निगरानी-प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, तो सरकारी योजनाएँ देश की उद्यमिता–विशेषकर गैर-मेट्रो एवं ग्रामीण क्षेत्र–को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टि से तेज़ी से उन्नत कर सकती हैं।

बीज शब्द

उद्यमिता, सरकारी योजनाएँ, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत, महिला उद्यमिता, आर्थिक विकास, MSME.

अंक-3, खण्ड-2, अप्रैल - जून 2025 E-ISSN : 2584-2900

प्रस्तावना

भारत एक युवा राष्ट्र है और यहाँ का जनसंख्या का बड़ा भाग कार्यशील है। भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में है जहाँ औसत आयु 29 वर्ष है; 2030 तक कार्य-बल में 60 कौटि (600 मिलियन) से अधिक युवा होंगे। इस जनशक्ति को उत्पादक दिशा देने के लिए उद्यमिता एक प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। उद्यमिता न केवल व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास में भी सहायक होती है। सरकार द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना तथा व्यवसायिक वातावरण को सुगम बनाना है। यह शोध पत्र इन्हीं योजनाओं के प्रभाव, लाभ, चुनौतियों एवं सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन करता है।

1. आर्थिक दृष्टि से - MSME क्षेत्र GDP का ~30 % और निर्यात का ~45 % योगदान देता है।
2. सामाजिक दृष्टि से–महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पूर्वोत्तर के उद्यमी, स्थानीय स्तर पर रोज़गार एवं अवसर सृजित कर सामाजिक गतिशीलता बढ़ाते हैं।
3. प्रौद्योगिकीय दृष्टि से - AI, IoT, Greentech तथा Agritech स्टार्ट-अप्स वैश्विक समस्याओं के स्थानिक समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।

सरकार ने 2015 के बाद से मुद्रा, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PM - GatiShakti, ONDC जैसी योजनाओं एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर - UPI, GEM, GSTN, Aadhaar - eKYC का निर्माण कर उद्यमिता-परिस्थिति को नए युग में प्रवेश कराया है। यह शोध पत्र इन पहलों के प्रभाव, अंतर्निहित बाधाओं और सुधारात्मक सुझावों का गहन विश्लेषण करता है।

शोध विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें द्वितीयक स्रोतों से जानकारी एकत्र की गई है जैसे - सरकारी रिपोर्टें, योजना दस्तावेज, शोध पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, तथा वेबसाइट्स। योजना विशेष के आंकड़ों, नीति दस्तावेजों और केस स्टडीज़ का अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

शोध विस्तार

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - इस योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 'शिशु', 'किशोर', और 'तरुण' श्रेणियों में विभाजित इस योजना ने लाखों छोटे व्यापारियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

2. स्टार्टअप इंडिया - इस योजना का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप्स को पूंजी, तकनीकी सहायता, एवं अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करना है। टैक्स छूट, फंडिंग, पेटेंट प्रक्रिया में सरलता आदि इसके प्रमुख पहलू हैं।

3. स्टैंडअप इंडिया - यह योजना अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। यह योजना सामाजिक समावेशिता एवं आर्थिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. आत्मनिर्भर भारत अभियान - कोविड-19 के दौरान शुरू की गई यह योजना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता को सशक्त बनाने पर बल देती है। MSMEs को वित्तीय पैकेज, नीति सुधार, श्रम कानूनों में बदलाव आदि के माध्यम से समर्थन दिया गया।

5. महिला उद्यमिता को बढ़ावा - महिला उद्यमिता विकास योजना, अनुसूचित जनजाति/जाति महिला उद्यमिता सहायता योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता एवं विपणन सहायता प्रदान की जा रही है।

6. चुनौतियाँ - उद्यमिता विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका में कुछ चुनौतिंयॉ सामने आती हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार है -

1. योजनाओं की जानकारी का अभाव
2. ऋण प्रक्रिया में जटिलता
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी
4. प्रशिक्षण और परामर्श की सीमित उपलब्धता

7. सुधार की संभावनाएँ - उद्यमिता विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका में सुधार की सम्भावनाएं हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार है -

1. योजनाओं के प्रचार-प्रसार में वृद्धि
2. डिजिटल साक्षरता में सुधार
3. एकल खिड़की प्रणाली का विकास
4. निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना

निष्कर्ष

सरकारी योजनाएँ भारतीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं ने न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं नवाचार को भी बल प्रदान किया है। मुद्रा और CGTMSE ने माइक्रो-स्तर पर पूँजी की दीवार तोड़ी; स्टार्ट-अप इंडिया ने वैश्विक-स्तर पर नवाचार को पहचान दिलाई; स्टैंड-अप इंडिया और महिला-केंद्रित पहलों ने उद्यमिता को समावेशी बनाया। इसके फलस्वरूप 2014-15 में जहाँ भारत का Ease of Doing Business रैंक 142 था, वहीं 2020 में 63 पर पहुँचा; स्टार्ट-अप वैल्यूएशन $350 बिलियन पार कर चुका है। हालाँकि, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, जिनके समाधान हेतु निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। एक समावेशी, पारदर्शी और जागरूक नीति प्रणाली के माध्यम से उद्यमिता को नई ऊँचाइयाँ दी जा सकती हैं।

फिर भी सफल आउटकम-आधारित क्रियान्वयन के लिए तीन मोर्चों पर सुधार जरूरी है:

1. सूचना एवं आउटरीच: ब्लॉक-स्तर पर डिजिटल-सहायक केंद्र एवं स्थानीय भाषा-आधारित मोबाइल-ऐप्स।
2. बैंक-सी भरोसा और क्षमता: बैंक कर्मियों के लिए MSME-विशेष क्रेडिट असेसमेंट प्रशिक्षण; वर्किंग-कैपिटल फाइनेंस को GST-डेटा से जोड़कर इंस्टैंट-स्कोरिंग।
3. मेंटोरशिप व मूल्य-श्रृंखला एकीकरण: उद्योग-अकादमिक-सरकार त्रिकोण से सांसद आदर्श ग्राम-जैसे मॉडल में क्लस्टर-आधारित मेंटर नेटवर्क; ONDC-आधारित मार्केट-लिंकेज।

यदि केंद्र एवं राज्य सरकारें इन सुधारों को समन्वित रूप से लागू करती हैं, तो 2030 तक भारत 10 लाख प्रगतिशील स्टार्ट-अप्स, 50 करोड़ सशक्त रोज़गार, तथा $5 ट्रिलियन डिजिटल-प्रमुख अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को सशक्त रूप से प्राप्त कर सकता है।

संदर्भ

1. भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME Reports)
2. www.startupindia.gov.in
3. www.mudra.org.in
4. नीति आयोग रिपोर्ट्स
5. आर्थिक समीक्षा 2023-24
6. Reserve Bank of India - SME और MSME डेटा
7. Times of India, The Hindu, Business Standard (2022-24 लेख)
8. विभिन्न शोध पत्र और जर्नल्स (Journal of Entrepreneurship Development, Indian Economic Review)